RAJYA SABHA

Tuesday, the 16*th December,* 2003/25 *Agrahayana,* 1925 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Debt Swap Scheme for States

*201. DR. T. SUBBARAMI REDDY:†
SHRI MOOLCHAND MEENA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether States have pre-paid Rs. 23,000 crore of high cost debts in the first seven months ending October 31, 2003 in the current financial year taking advantage of the debt-swap scheme;

(b) if so, whether this pre-payment will also help States in decreasing funds and improving State finances; and

(c) if so, to what extent States have pre-paid their debts uptill now?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI JASWANT SINGH): (a) to (c) A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir. States have pre-paid an amount of Rs. 33,507.50 crores of outstanding high cost Government of India loans during the current year upto end of October, 2003.

(b) Yes, Sir.

(c) High cost debt of Government of India, amounting to Rs. 49,818 crores has been pre-paid by the States uptill now.

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. T. Subbarami Reddy.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Finance Minister this. In our country, in almost all the States, or in major States, there are financial crises. I welcome this Debt Relief Scheme, which is being planned by the Government. But here, I would like to know which are the States where the progress is very much hampered due to financial crises and how to come out from the problem. Are they suffering because of the heavy interest burden or due to too much subsidies being given to various schemes? Ultimately, what is the Government's plan to bail out states like Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh and so many other big States in the country where there are financial crises? May I know from the Finance Minister as to what are the crises, and how they are going to solve the problem? As on today, how this debt relief scheme, by reducing the burden of interest, is going to bail out the states to some extent?

SHRI JASWANT SINGH: Sir, the hon. Member has asked rather an omnibus question. The very purpose of the Debt Swap Scheme for States is to ameliorate the difficulties of the States on account of the heavy burden of debt. We had set out ourselves the target in the Ministry of Finance when I started the scheme of doing debt swap of Rs. 114,000 crores in a three-year period. I am very glad to share with the House that, in fact in a one-year period , spread over two financial years of that 100 odd thousand crores of rupees, we have reached almost the Rs. 50,000 crores mark of swapping high-cost debt. In the balance two-three months, I expect to reach another Rs. 10-12,000 crores. So we will have a total of Rs. 62,000 crores of debt swap against Rs. 114 thousand which was to be done in three years. The hon. Member wanted to know what are the difficulties that some states are experiencing in this regard. Now, of course, all the States are participating. In the beginning, Maharashtra did not wish to participate because of various reasons. I do not wish to analyse the finances of each and every State here in the House. It is also not the purpose of the question. But the difficulties that some States have expressed are in regard to a possible liquidity shortage that they may face on account of the Debt Swap Scheme being linked so closely to the small savings. This is broadly the answer to the hon. Member's question.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Mr. Chairman, I am happy, the hon. Finance Minister on 14th, that is, day before yesterday, announced that

he was planning to have a package for this. He said that "We are working out on a comprehensive debt swap plan which will be implemented in a phased manner. The intention is to bring down the States' debt to Rs. 44,000 crores." This is a welcome measure that you have announced, but not elaborated. May I know from the Finance Minister what is the plan, what is the scheme to bring down this to Rs. 44,000 crores?

SHRI JASWANT SINGH: Sir, it is one of the axioms of good governnance that before a scheme has full matured, it would be highly unwise of me to share what the contours or the contents of the scheme are. I would request the hon. Member to keep watching this pace in the next two-three months and see what developments take place.

श्री मूल चन्द मीणा: सभापति महोदय, अदला-बदली ऋण योजना का लाभ राज्यों ने उठाया है और इसके आधार पर पूर्व भुगतान हुआ है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राज्यों पर अब तक पूर्व भुगतान के बाद और कितना बकाया है और यह स्कीम कब तक चलती रहेगी? राज्य अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके, सुधार कर सकें, इसके लिए क्या सरकार की और कोई दूसरी प्रभावशाली योजना प्रारंभ करने की है?

श्री सभापति: इसको तो लागू होने दीजिए।

श्री जसवंत सिंह: सभापति जी, मैं प्रश्न का पहले जवाब दे चुका हूं। हमारी यह स्कीम तीन साल की अवधि के लिए थी। अभी जैसा मैंने माननीय सदस्यों को बताया, हमारा लक्ष्य था कि तीन साल के भीतर एक लाख 14 हजार करोड़ के राज्यों के जो ऋण हैं उनकी अदला-बदली कीजिए जिससे उन पर ब्याज का जो अधिक दबाव है वह उससे कम हो और साल भर के भीतर ही दो फाइनेंशियल इयर में एक लाख 14 हजार करोड़ में से हमने करीब 50 हजार करोड़ इस साल के अंत तक 62 हजार करोड़ हम कर देंगें। इससे राज्यों को निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ है।

श्री दत्ता मेघे: महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्टरेस्ट कम करने की दृष्टि से कोई योजना भेजी है और दूसरे जो वर्ल्ड बैंक का जो लोन था वह अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक का जो लोन था वह अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक देने को तैयार है। केन्द्र सरकार ने उस लोन के लिए मंजूरी दी या नहीं?

श्री जसवंत सिंह: सभापति जी, माननीय सदस्य सीधे महाराष्ट्र से आते हैं लेकिन माननीय सदस्य डेट स्वैप से वर्ल्ड बैंक के रास्ते चले गए हैं। मैं उन्हें डेट स्वैप वापस ले आता हूं।

श्री सभापति: बहुत बड़ी जगह है, जाने दीजिए ना। आप क्यों वापस लाते हैं।

श्री संजय निरुपम: फाइनेंशियल कैपिटल ...**(व्यवधान)**...

श्री जसवंत सिंह: फाइनेंशियल कैपिटल कठिनाइयों में था। देखिए, वित्त मंत्रालय में किसी राज्य सरकार के साथ किसी प्रकार का भेद-भाव का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था है वह राजनैतिक तौर पर विभाजित नहीं हो सकती और वित्त मंत्रालय करता है। रहा महाराष्ट्र का सवाल। महाराष्ट्र को कठिनाइयां हैं। उनके मुख्य मंत्री जी से मैं बात कर चुका हूं। पिछले साल महाराष्ट्र ने इस स्कीम होने से इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र राज्य पर एक और जो बड़ी कठिनाई है वह है कि वहां बहुत ज्यादा स्टेट गारंटी दी जा चुकी है, करीब 60 हजार करोड़ की। कोई भी राज्य इस प्रकार की स्टेट गारंटी देगा तो यह मानकर चलिए कि कठिनाई उत्पन्न होगी। इस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार के साथ और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के साथ हमारा वित्त मंत्रालय निरंतर इस समस्या को सुलझाने के लिए लगा हुआ है।

SHRI P.G. NARAYANAN: Mr. Chairman, Sir, the financial position of the States has been in a very critical state for the last several years. The United front Government has already promised that 29 per cent of the tax revenues will be devolved on the States. In view of the precarious financial position of the State Government, and the fact that the State Governments have to implement a lot of welfare schemes, will the Centre consider devolving at least, 50 per cent of the tax revenues on the State Governments?

SHRI JASWANT SINGH: Sir, this is not the decision that is within the purview of the Ministry of Finance, or what the hon. Member rather broadly calls the 'Centre'. Should the political authorities of the country wish to increase the devolution percentage to the States, then forum for that is not this. Please make your submissions to the Finance Commission, which is currently in operation, and also the National Development council. I can give no such assurance to the hon. Member.

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस अदला-बदली योजना में अब तक कितने राज्यों ने अपने आपको शामिल किया है और इस अदला-बदली योजना में किस राज्य की तरफ अभी भी काफी ऋण बकाया है, जिसकी अदला-बदली नहीं हो सकी है?

श्री जसवंत सिंह: सभापति जी, मैं, इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। पिछले साल महाराष्ट्र इसमें शरीक नहीं हुआ था, अब सभी राज्य इसमें शरीक हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है जो इस अदला-बदली स्कीम का लाभ नहीं उठाना चाहता है।

श्री मोती लाल वोरा: सभापति जी, मैंने पूछा है कि अभी किस राज्य पर ज्यादा ऋण बकाया है, जिसकी आपकी योजना के अंतर्गत अदला-बदली नहीं हो सकी है।

श्री जसवंत सिंह: सभापति जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सभी राज्यों के ऋण पढ़कर सुना दूं।

श्री मोती लाल वोरा: मैंने एक राज्य के बारे में पूछा है कि किस राज्य का सबसे ज्यादा बकाया है। आपके पास एक-दो राज्यों का होगा। माननीय मंत्री जी विवरण लाए होंगे।

श्री सभापति: पूरी लिस्ट है।

श्री मोती लाल वोरा: मैं पूरी लिस्ट या हर राज्य के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, केवल एक राज्य के बारे में पूछ रहा हूं कि अभी तक किस राज्य पर अदला-बदली योजना का सर्वाधिक ऋण बाकी है, जिस राज्य ने इसका लाभ नहीं उठाया है।

श्री जसवंत सिंह: सभी राज्य लाभ उठा रहे हैं, हर राज्य ने लाभ उठाया है। अगर राज्यों के ऋण की स्थिति के बारे में माननीय सदस्य वास्तव में जानना चाहते हैं इसे हम आप तक पहुंचा देंगे।

श्री ललितभाई मेहता: सभापति जी, राज्यों के बजट का सोलह प्रतिशत ब्याज का भुगतान अभी तक होता रहा था, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि इस अदला-बदली योजना के कारण राज्यों पर जो ब्याज का बोझ है क्या वह कम होने जा रहा है? केन्द्र सरकार के बजट के ब्याज का भुगतान इकतीस प्रतिशत होता रहा है। राज्यों द्वारा जो विकास का खर्च हो रहा है वह केन्द्र सरकार के विकास के खर्च से लगभग दुगुना हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्या कारण है केंद्र सरकार के विकास का खर्च कम हो रहा है, और राज्यों को विकास के खर्च के लिए कितनी अधिक राशि उपलब्ध हो पाएगी?

श्री जसवंत सिंह: सभापति जी, यह प्रश्न इससे जुड़ा हुआ नहीं है। योजना आयोग, राज्यों की आर्थिक स्थिति आदि तथा इसमें अन्य कई पहलू हैं। माननीय सदस्य दूसरे प्रश्न को पूछें।

Management of Kolkata Stock Exchange

*202. SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have noticed deficiencies in the management of Kolkata Stock Exchange;